3 छग सरकार कर रही है पर्यटन विकास

5 जनहित कार्यों के लिये चर्चित हैं आतिशी

7 पत्रकारों का महाअधिवेशन आलोट में

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 35 प्रति सोमवार, 6 जनवरी 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ संज्ञान?

व्हिसल ब्लोअर एवं पत्रकार राजीव सिंह भदौरिया के खिलाफ शासन ने दर्ज किये अवैध आपराधिक मामले, उनकी हत्या की आशंका

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की क्या स्थिति है। लोकायुक्त की जांच सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अभयदान कैसे देती है, इसका एक उदाहरण राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक अखबार ने अपनी मुख्य आवरण कथा में हैडिंग के साथ छापा 'ईडी भी हैरान-लोकायुक्त ने आरोपियों के बचने के रास्ते क्यों छोड़े, न कार पकड़ी, न सहयोगी के घर छापा मारा'। यह मामला अभी ताजे सौरभ शर्मा परिवहन घोटाले को लेकर प्रदेश के लोकायुक्त जैसे संस्थान की कार्य प्रणाली का एक छोटा सा अंश भर है। अगर कोई शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ हो तो उसकी क्या जॉच होगी? यह सोचने वाली बात है। ऐसा ही कुछ काम लोकायुक्त ने उज्जैन स्थित पत्रकार राजीव सिंह भदौरिया की दिनांक 5/10/2023 की शिकायत पर भी किया है, हो सकता है कि मामले को लोकायुक्त ने नस्तीबद्ध भी कर दिया हो। मध्यप्रदेश की जॉच एजेंसियों के कारण एक पत्रकार (राजीव सिंह भदौरिया) को अपनी जान बचाने के लिये जतन करने पड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह लोकायुक्त ने महाकाल लोक घोटाले को लेकर भी किया था। लोकायुक्त का लचर रवैया हाल ही में परिवहन विभाग के एक कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में भी देखा जा सकता है। लोकायुक्त कैसे-कैसे हथकंडे अपनाकर सौरभ शर्मा और उससे जुड़े रसूखदार लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। जब मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगी? सवाल बड़ा है और इसका जवाब हम जानना चाहते हैं।

बीजेपी शासन में लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली पर लगा प्रश्नचिह्न

लोकायुक्त की निष्पक्षता पर भी उठने लगे हैं सवाल

मोहन सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगा पहरा

अभी हाल ही में भोपाल स्थित कुछ पत्रकारों को मोहन यादव सरकार के खिलाफ छापने के कारण उनको आवंटित शासकीय आवास खाली कराने के नोटिस भी प्राप्त हुए हैं। और कुछ पत्रकारों की अधिमान्यता भी निरस्त कर दी गई है। ऐसे में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ ऐसी शिकायतों का संज्ञान स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करना चाहिए या फिर माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री समेत 10 विभागों के मंत्री मोहन यादव के खिलाफ प्रदेश की कोई भी जॉच एजेंसी निष्पक्ष जॉच की स्थिति में नहीं है।

(शेष पेज 2 पर)

सौरभ शर्मा के पीछे आखिर कौन है असली धनकुबेर, क्या मोहन सरकार इन धनकुबेरों को दिला पायेगी सजा?

(विस्तृत पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की लापरवाही से गई एक कलम के सिपाही की जान

आखिर कौन लेगा मुकेश चंद्राकर की मौत की जिम्मेदारी, क्या सरकार पत्रकार को दिला पायेगी न्याय?

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजधानी एक बार फिर शर्मसार हो गई है। जनता की सुरक्षा के बड़े बड़े वायदे करने वाले गृहमंत्री विजय शर्मा के सभी वायदे हवा हो गये और एक बेगुनाह पत्रकार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण में गड़बड़ी और कथित घोटाले की पोल खोलने वाले साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। चंद्राकर वह पत्रकार थे,

▪ पत्रकार मुकेश चंद्राकर

▪ गृहमंत्री

जिन्होंने कोबरा बटालियन के अगवा जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों के साथ वार्ता की पहल और मध्यस्थता की थी और जवान को छुड़ाकर ले आए थे। उनकी हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुकेश चंद्रकार की हत्या हुई है। उनके रिश्तेदार ही इस मामले में आरोपी हैं। (शेष पेज 3 पर)

राज्य के पत्रकारों में खासा रोष

बीजापुर में हुई इस हत्या के बाद पत्रकारों में नाराजगी है। पत्रकारों ने बीजापुर नेशनल हाइवे नंबर 63 पर चार घंटे तक चक्काजाम किया। वहीं, रायपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और वुमेन प्रेस कॉर्प्स की ओर से भी इस घटना की गहरी निंदा की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ संज्ञान?

(पेज 1 से जारी)

मुख्यमंत्री मोहन ने रखे अनुभवहीन सलाहकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सलाह के लिए ऐसे लोगों की टीम तैयार कर रखी है जो अनुभवहीन के साथ-साथ गलत सलाह देकर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सलाहकारों की सलाह पर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका कोई आधार ही नही बनता है। और ऐसे फैसले मुख्यमंत्री की छवि आम जनता के बीच में धूमिल कर रहे हैं। आईएएस भरत यादव और मुख्यमंत्री के करीबी कई अधिकारी इस टीम का हिस्सा हैं। किसी भी पत्रकार की अभिमान्यता खत्म करना उसकी पत्रकारिता पर कुठाराघात है। इस कदम का मतलब है कि पत्रकारों के बीच खौफ पैदा करना ताकि अन्य कोई पत्रकार भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सच्चाई प्रकाशित न कर सके।

मुख्यमंत्री बनने से पहले मोहन यादव ने की थी कई अनियमितताएं, नियम कायदों को रखा ताक पर

दरअसल पत्रकार राजीव सिंह भदौरिया ने अपनी 09 पेज की शिकायत समेत कुल 65 दस्तावेज लोकायुक्त को मध्यप्रदेश के तत्कालीन उच्च शिक्षामंत्री मोहन यादव के खिलाफ दिये थे। जिसमें विषय ''उच्च शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं पूर्व अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहते संचालक मण्डल के अनुमोदन के बिना, अंकेक्षण सहित अन्य विभागों की सतत आपत्ति के बावजूद नियम विरूद्ध तरीके से कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने, योजनाओं में हेरफेर कर औने-पौने दामों पर जमीन क्रय कर लगभग 500 बीघा की अवैध संपदा बनाने, प्राधिकरण से कथित समझौता के नाम पर संस्था की भूमि अधिग्रहित कर भू-खण्ड बेचकर राजस्व की क्षति पहुंचाने व घोर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कदाचरण करने के मामले में संज्ञान लेकर दस्तावेज तलब कर प्रकरण दर्ज करने हेतु'', एक शिकायत लोकायुक्त भोपाल को सौंपी थी। इस शिकायत में पत्रकार राजीव सिंह भदौरिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ पद, प्रभाव, अधिकार का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करके अकूत धन संपत्ति एकत्रित करने की शिकायत सबूतों सहित लोकायुक्त में जमा कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 06 करोड़ 20 लाख की राशि गैर योजना मद से खर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा राशि के लिये या कोई स्वीकृत कार्य 7.50 करोड़ से ज्यादा का होता है तो निविदा सूचना आमंत्रण के 15 दिवस पहले ही शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा 23/11/2007 में डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ब्रिज जिसे सांवरासेढ़ी ब्रिज भी कहा जाता है, के लिये निविदा आमंत्रित की गई। दिनांक 16/01/2008 को फेरो कांक्रिट कंस्ट्रेक्शन (इंडिया प्रायवेट लिमिटेड) के पक्ष में निविदा खुली। जिसका मूल्य 8.95 करोड़ था। सवाल यह उठता है कि तब के तत्कालीन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कावडिया की आपत्ति को दरकिनार कर ठेका उक्त कंपनी को दे दिया गया। राजीव सिंह भदौरिया द्वारा सूचना के अधिकार में दस्तावेज कार्य की दर रुपये 8.95 करोड़ की कोई स्वीकृति 28/03/2008 की बोर्ड बैठक में नहीं ली गई। इस पर सिर्फ चर्चा की गई। कावडिया ने अपनी जो आपत्ति लिखित पत्र द्वारा प्राधिकरण को सौंपी थी उसमें यह आरोप लगाये थे कि कार्य हेतु बोर्ड की स्वीकृति के बिना संबंधित ठेकेदार को कार्य आदेश सौंप दिया गया, विज्ञप्ति में 08 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति की गई जबकि शासन से 6.20 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अलावा कावडिया ने यह भी सुझाव दिया था कि ब्रिज का निर्माण प्राधिकरण की निधि के बजाय केन्द्र शासन की योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की मद से बनाया जाये। तत्कालीन उपाध्यक्ष कावडिया ने स्पष्ट किया था कि बढ़ी हुई राशि की स्वीकृति संचालक मण्डल से नही ली गई थी इसके वह स्वयं भी सदस्य थे। कावडिया की उक्त आपत्तियों को नोटशीट में प्रचलित किया गया। इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरके शर्मा ने पत्र क्रमांक आर.ए.डी.-4 दिनांक 08/04/2008 में लिखा कि ''मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3/74/05/32 भोपाल दिनांक 24/02/2007 को पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें कि बजट वर्ष 2006-07 में गैर योजना मद के अंतर्गत राशि 6.20 करोड़ की स्वीकृति जो की जाती है कि राशि रुपये 3.00 करोड़ वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की जानी थी, उक्त दोनों वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने व्यय करने वाली राशि को पुर्नरीक्षित स्वीकृति प्रदान करना एवं 2.75 करोड़ जो कि स्वीकृत मद एवं कार्यादेश राशि का अंतर है उसकी प्रतिपूर्ति कैसे की जायेगी''। दिनांक 16/04/2008 को उज्जैन विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष मोहन यादव ने पत्र जारी कर सारी शिकायतों को नियम विरुद्ध दरकिनार कर दिया। बाद में सांवरासेढ़ी ब्रिज के निर्माण में कुल 10 करोड़ का खर्चा हुआ। इसके साथ ही राजीव सिंह भदौरिया ने आशियाना इनफ्रोटेक, अम्बेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित एवं कई तथ्यात्मक आरोप तत्कालीन अध्यक्ष मोहन यादव के ऊपर लगाये। इनसे संबंधित दस्तावेज भी शिकायत के साथ लोकायुक्त को जमा किये गये थे। उल्लेखनीय है कि इस शिकायत में पृष्ठ क्रमांक-8 में बताया गया कि सांवरासेढ़ी ब्रिज योजना के दौरान स्वयं मोहन यादव, उनका परिवार एवं खास लोगों ने सांवरासेढ़ी में तकरीबन 500 बीघा के अधिक भूमि खरीद ली थी। साथ ही 5000 करोड़ की धन संपत्ति का आरोप भी शिकायत में लगाया गया। राजीव सिंह भदौरिया ने पृष्ठ क्रमांक-9 में अपने साथ अप्रिय घटना होने की आशंका भी जताई थी जो कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में सत्य साबित हुई, जहां उनके ऊपर अनेक आपराधिक मामले दर्ज कर उनके खिलाफ जिलाबदर की कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जा रही है। भदौरिया कुछ दिनों से गायब हैं। आशंका है कि उनके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो?

मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही मोहन यादव ने पत्रकार को घर से उठवा लिया

यह वाक्या भी हमें झकझोर कर देने वाला है। कैसे कोई मुख्यमंत्री अपने उपर आरोप लगाने वाले पत्रकार को खत्म कर सकता है दरअसल जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके तुरंत बाद ही पत्रकार राजेन्द्र सिंह को घर से उठवा लिया गया था और उन पर कई झूठे गंभीर आरोप लगाकर जिला बदर तक करवा दिया गया था। जब पत्रकार को कोर्ट से बेल मिल गई थी उसके बाद भी उनके खिलाफ 5-6 नये केस दर्ज करवा दिये गये। यहां तक कि राजेन्द्र सिंह का घर तक तुड़वा दिया और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।

भोपाल में लोकायुक्त का अब तक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा, 52 तोला सोना हुआ जप्त

-विजया पाठक

(पेज 1 का विस्तृत)

मध्यप्रदेश में इन दिनों लोकायुक्त टीम खासी सक्रिय है। तीनों ही जांच दलों की टीमों ने प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के जाल से पर्दा उठा कर राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। 18 दिसंबर को लोकायुक्त ने सौरभ के आवास पर छापा मारा था। छापे में सौरभ और उसके करीबी चेतन के ई-7 भोपाल स्थित आवास से आठ करोड़ रुपये की संपत्ति मिली थी। इसके दूसरे ही दिन मेंढोरी गांव में एक प्लाट में खड़ी चेतन की कार में 54 किलो सोना और लगभग 10 करोड़ रुपये नकद मिले थे। इसके बाद शंका जाहिर की जा रही थी कि लोकायुक्त छापे की सूचना लीक हुई है। ऐसे में आगे सूचना लीक न हों, इस दृष्टि से इस बदलाव को देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश के धनकुबेर सौरभ शर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें उनके घर और सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी और अन्य संपत्ति बरामद हुई है। सौरभ शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस धनकुबेर के पास इतना धन आया कहां से, कौन है इस धन के असली मालिक, क्या मोहन सरकार असली धनकुबेरों को दिला पायेगी कड़ी सजा?

सौरभ की मां के बयान ने उड़ाये होश

सौरभ शर्मा की मां ने इस मामले में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, "मैं ग्वालियर में रहती हूं और सौरभ से संपर्क नहीं हो पाया है। मुझे नहीं पता वह कहां है।" उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कह सकतीं, क्योंकि वह यहां नहीं रहती थीं। सौरभ की सफाई में उनका कोई बयान नहीं था जब सौरभ के बारे में पूछा गया, तो उनकी मां ने कहा कि वह चेतन को जानती हैं, लेकिन सोना और पैसा किसका है, यह उन्हें नहीं पता। उन्होंने बताया कि सौरभ की जान को खतरा है और जमानत याचिका भी उन्होंने लगाई थी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि उनकी तबियत खराब है और इलाज नहीं हो पा रहा है।

ईडी की कार्यवाही और बरामदगी

ईडी ने सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह के घर पर छापा मारा, जहां से पैसों के लेन-देन की फाइलें, नोट गिनने की मशीन और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। सौरभ की पत्नी, शरद जायसवाल और चेतन के नाम की भी फाइलें मिलीं। इन फाइलों में करोड़ों के लेन-देन का लेखाजोखा था, साथ ही रिसॉर्ट और मस्तस्य विभाग के टेंडर से संबंधित दस्तावेज भी मिले. इसके अतिरिक्त, सील और ATM कार्ड भी बरामद किए गए।

ईडी की कार्यवाही का विस्तार

पिछले दिनों भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में ईडी की रेड चल रही थी, जिसमें सौरभ शर्मा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। भोपाल में चार जगहों पर छापेमारी हुई, जिनमें सौरभ के नए बंगले और उनके बिजनेस पार्टनर शरद जायसवाल के घर भी शामिल थे। शरद फिलहाल फरार हैं और बताया जा रहा है कि वह दुबई में हैं। सौरभ के ठिकानों के आसपास पुलिस ने CCTV कैमरे लगाए हैं और पड़ोसियों से फुटेज भी जब्त किए हैं. पुलिस ने 16 दिसंबर और 19 दिसंबर के फुटेज से कुछ अहम जानकारी जुटाई है।

अब तक बरामद संपत्ति

52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये की नकदी इनोवा क्रिस्टा कार से।

सौरभ के घर से 3 करोड़ रुपये नकद और कीमती गहने।

चेतन के घर से 234 किलो चांदी और 4 करोड़ रुपये नकद।

कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डायरी।

इधर आरक्षकों के तबादलों से उठे प्रश्न

पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के आवास पर छापेमारी में मिली करोड़ों की संपत्ति के बाद अब विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाया गया है। अब डीजी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने मुख्यालय व जोनल इकाइयों में पदस्थ चार एएसपी, छह इंस्पेक्टर और 24 कॉन्स्टेबलों के तबादले के आदेश के साथ ही तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है।

परिवहन विभाग में किये थोकबंद तबादले

पिछले ही दिनों परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा पर कार्रवाई ने इसे चर्चा में ला दिया है। अब मध्यप्रदेश सरकार ने इस विभाग में बड़ा फेरबदल करके कुछ तबादले कर दिए हैं। लोकायुक्त में लंबे समय से पदस्थ चार डीएसपी, छह निरीक्षक और 24 कॉन्स्टेबल को एक ही दिन में हटा दिया गया है। इन सभी को पुलिस मुख्यालय और अन्य पुलिस इकाइयों में भेजा गया है। आने वाले दिनों में कई अधिकारियों, कर्मचारियों के थोकबंद तबादले और हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी लोकायुक्त में कुछ डीएसपी और निरीक्षक तीन वर्ष से भी अधिक समय से पदस्थ हैं।

ग्रामीणों ने की समूहों पर कार्रवाई की मांग

तीतरपानी गौशाला में गायों को खिलाया जा रहा गन्ने का छुकला एवं सोयाबीन के डंठल

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकलां। सड़कों पर घूमते गौवंशों को आश्रय देने को गोशाला तो बना दी गई हैं और गौवंश के संरक्षण के लिए अभियान तो चलाए जाते हैं गौशालाएं भी बनाई गई हैं लेकिन इन्हीं गौशालाओं में यह गायें सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस मामले पर संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने की जरूरत है। और इसी गंभीर मामले को लेकर के आप तस्वीरों को देखकर स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि गायों की दुर्दशा क्या है। क्या व्यवस्थाएं गौशाला संचालक द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि देवरी विकासखंड अंतर्गत तीतरपानी गौशाला में गोवंश को खिलाया जा रहा सोयाबीन के डंठल और सूखा भूसा। मीडिया टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान खुली पोल। जबकि नियम अनुसार हरा चारा, सूखा चारा जैसे गेहूं का भूसा, मक्का या ज्वार की कड़वी, अरहर की भूसी, दाना, मिनरल मिक्सचर, नमक, गुड़, चोकर आदि गोवंश को आहार उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन सागर जिले के देवरी विकासखंड अंतर्गत तीतरपानी गौशाला में गौवंश की ठीक से देखरेख नहीं हो रही। उन्हें न तो मानक के अनुरूप आहार दिया जा रहा और न ही समुचित सफाई व्यवस्था की जा रही। सूखे भूसे के कारण गोवंश अत्यंत कमजोर हो रहे हैं। इसकी वजह से गोवंश दम तोड़ देते हैं।

तीतरपानी गौशाला में गायों की संख्या करीब 90 से अधिक है। वहां मीडिया द्वारा निरीक्षण में पता चला कि गोवंश को सुखा भूसा दिया जा रहा है, और गौशाला में समूह द्वारा साफ सफाई नियमित रूप से नहीं की जा रही है, कुछ गौ वंश तो वहां पर कमजोर नजर आये। और ना ही तो गौशाला में कभी कोई कर्मचारी नजर आता है बाहर से गौशाला संचालक द्वारा ताला डाल दिया जाता है और वह अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हैं। आपको बता दे कि गौशाला का संचालक के यहां पर गुड़ का व्यवसाय है जिसके चलती गायों के लिए गन्ने के छिलके खिलाने के लिए डाल दिए जाते हैं। तीतरपानी गौशाला संचालक द्वारा गायों के प्रति भारी लापरवाही बरती जा रही है। ग्राम के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने बताया कि तीतरपानी गौशाला संचालक द्वारा गायों के प्रति देखरेख करने की भावना नहीं है जिस कारण से गायों के लिए भरपेट आहार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और सोयाबीन की फसल के डंठल खिलाये जा रहे हैं। और गौशाला संचालक के यहां पर गुड़ का व्यवसाय चलता है। जो गन्ने के छिलके उसमें से निकलते हैं वहीं गायों के लिए आहार के रूप में दिया जा रहा है जो शासन के नियम अनुसार आहार रहता है वह बिल्कुल भी आज तक नहीं दिया गया है।

इनका कहना कि

उन्हें बताया भी था साफ-सफाई रखें। यदि उनके द्वारा सुधार नहीं किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जावेगी।

-डॉ. महेंद्र पटेल, पशुपालन विभाग, देवरी

(जगत फीचर्स)

छग के गृहमंत्री विजय शर्मा की लापरवाही से गई एक कलम के सिपाही की जान

(पेज 1 से जारी)

बताया गया है कि उनका शव उनके रिश्तेदार के बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में मिला है। शव को छिपाने के बाद टैंक को चार इंच कंक्रीट से ढलाई कर पैक कर दिया गया था। मुकेश चंद्रकार एक जनवरी से लापता थे।

पत्रकार की मौत पर शुरू हुई सियासत

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उधर भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि हर बार अपराध में कांग्रेस के नेता ही क्यों पकड़े जाते हैं? गौरतलब है कि आरोपियों का कांग्रेस के साथ संबंध रहा है। लेकिन इन आरोपों का जवाब देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ही पीडब्लुडी मंत्री हैं और उनके विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार की हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की खस्ताहालत को लेकर खबर बनाई थी और इसमें घोटाले का पर्दाफाश किया था।

क्या खबर बनी मुकेश की मौत की वजह?

अपना यूट्यूब चैनल 'बस्तर जंक्शन' चलाने के साथ मुकेश विभिन्न मीडिया संस्थानों के लिए भी स्वतंत्र रूप से काम किया करते थे। बताया गया है कि इन दिनों वे 'एनडीटीवी' से जुड़े थे। बीते 24 दिसंबर को एनडीटीवी पर बस्तर में हो रहे एक सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रायपुर स्थित एनडीटीवी के पत्रकार निलेश त्रिपाठी की लिखी उस रिपोर्ट से मुकेश भी जुड़े थे। यह सड़क बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गंगालूर से नेलसनार तक बनाई जा रही थी।

धरती आबाः जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला 6 जनवरी को

-शशि पाण्डे

जगत प्रवाह. रायपुर। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा 'धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर संबंधित विभागों एवं अशासकीय संस्थानों के मध्य परिचर्चा-परामर्श हेतु एफईएस एवं एटीआरईई संस्था के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला न्यू सर्किट हाऊस, सिविल लाईन्स, रायपुर में होगा। आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने पत्र जारी कर सभी जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग जिला परियोजना समन्वयक के साथ कार्यशाला में उपस्थित रहने को कहा है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को धरती आबा- जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान अंतर्गत 17 मंत्रालयों के सहयोग से भारत सरकार की 25 योजनाओं को सुसंगत तरीके से धरातल पर उतारना है जिसमें वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन अंतर्गत मुख्य रूप से निश्चित समयावधि में वन अधिकारों की मान्यता की प्रकिया को पूर्ण किया जाना है। विभिन्न मंत्रालयों (जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मतस्य विभाग, पशुपालन विभाग इत्यादि) के योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वननिवासी जनजातीय परिवारों के सतत आजीविका की सुरक्षा, परस्थितिकीय संतुलन हेतु वनों की सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण एवं प्रबंधन इत्यादि जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति शामिल है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में अब तक 4 लाख 79 हजार 502 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन के अंतर्गत 4377 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 2081 सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत अधिकारों की मान्यता, वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण, अभिसरण से आजीविका संवर्धन आदि संपूर्ण कार्यों के बेहतर कियान्वयन हेतु संबंधित शासकीय विभागों तथा अशासकीय संस्थानों की सतत् भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन स्थल के रूप में कर रही है विकसित

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन और ऐतिहासिक, धार्मिक व पौराणिक महत्व के स्थलों को चिन्हांकित कर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत पर्यटन और रोमांच से भरपूर सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। इस पर्वत का ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां विशाल मेला का आयोजन भी होता है। महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन युवाओं के लिए एक शानदान डेस्टिनेशन है। यह स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्त्व के लिए जाना जाता है। राजधानी रायपुर से 157 किमी और सरायपाली से लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित यह पर्वत पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। शिशुपाल पर्वत (बूढ़ा डोंगर) समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए रोमांचक ट्रैकिंग मार्ग है, जो रोमांचक ट्रैकिंग का नया अनुभव कराता है। यह पर्यटन स्थल साहसिक गतिविधियों के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ट्रैकिंग मार्ग घने जंगलों, चट्टानों और प्राकृतिक पगडंडियों से होकर गुजरता है। पहाड़ के ऊपर एक विशाल मैदान है, जहां से

ऐतिहासिक लोककथाओं से जुड़ा है पर्वत का नाम

वर्षा ऋतु के दौरान पानी 1100 फीट नीचे गिरकर घोड़ाधार जलप्रपात का निर्माण करता है। यह झरना और उसके चारों ओर हरियाली एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए, दो साल पहले पर्यटन मंडल ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की। यहां पहुंचने वाले सैलानियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया, जिससे उनकी यात्रा सुखद और आरामदायक हो सके। शिशुपाल पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। यहां का वातावरण, झरने की आवाज, ठंडी हवा एवं प्राकृतिक सुंदरता व शांति का संगम पर्यटकों को मानसिक शांति और सुकून का अनुभव कराती है। यह स्थान फोटोग्राफी और प्रकृति के अद्भुत दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। शिशुपाल पर्वत न केवल रोमांचक ट्रैकिंग स्थल है, बल्कि इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम भी है। यह स्थान ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और इतिहास का अनुभव करना चाहते हैं, तो शिशुपाल पर्वत आपकी सूची में होना चाहिए। अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक आकर्षण के साथ, शिशुपाल पर्वत आज के दौर में पर्यटन का नया केंद्र बनता जा रहा है। शिशुपाल पर्वत पर्यटन स्थल में हर वर्ष मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में भक्त दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। इस दौरान मंदिर के आसपास भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ मेले की चहल-पहल का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति पर लगने वाला यह मेला इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिकता, साहसिक पर्यटन का अद्भुत अनुभव इसे एक संपूर्ण पर्यटन स्थल बनाता है। यह मेला न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि दूर-दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहा है।

सम्पादकीय

नई पीढ़ी को रामायाण की शिक्षा देने महाराष्ट्र के मंत्री का प्रशंसनीय कदम

देश की नई पीढ़ी को रामायण की शिक्षाओं को गहराई से समझाने और अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिये शुरू हुआ रामायण सांस्कृतिक केंद्र भारत के उदीयमान पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसका उद्देश्य न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करना है, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन और अन्य विकास कारकों को भी बढ़ावा देना भी है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष और देवेंद्र फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बताते हैं कि रामायण को नई पीढ़ी के लिए जीवंत बनाने के उद्देश्य से इस रामायण सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है।नागपुर के निकट कोराडी मंदिर परिसर स्थित रामायण सांस्कृतिक केंद्र चन्द्रशेखर बावनकुले का विजन रहा है। यह रामायण सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय विद्या भवन के उपाध्यक्ष और ट्रस्टी बनवारी लाल पुरोहित के दिमाग की उपज है। इस केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अत्याधुनिक तकनीक और परंपरा के प्रति श्रद्धा के साथ रामायण सांस्कृतिक केंद्र एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। आगंतुक आधुनिक प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के माध्यम से रामायण की शिक्षाओं को गहराई से समझ सकते हैं, जिससे भारत की आध्यात्मिक जड़ों से उनका गहरा जुड़ाव होगा। यही नहीं, पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने भारत के सांस्कृतिक गौरव के पुनरुत्थान का संकेत दिया और रामायण सांस्कृतिक केंद्र इस भावना को और आगे बढ़ाता है।

चंद्रशेखर बावनकुले का नेतृत्व इस पहल का केंद्र रहा है जो यह सुनिश्चित करता है कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बने। इस केंद्र में इमर्सिव डिजिटल डिस्प्ले, ऐतिहासिक कलाकृतियां और शैक्षिक अनुसंधान के लिए स्थान हैं, जो इसे एक सांस्कृतिक एपीसेंटर बनाता हैं जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष और देवेंद्र फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का विजन बुनियादी ढांचे से परे है। यह एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जो शिक्षित करता है, प्रेरित करता है और एकजुट करता है। संसाधनों को जुटाने और सामग्री को क्यूरेट करने में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि रामायण कल्चरल सेंटर केवल एक परियोजना नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक विरासत है। चंद्रशेखर बावनकुले का आग्रह है कि युवाओं और बच्चों को रामायण सांस्कृतिक केंद्र अवश्य देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

सियासी गहमागहमी

किसके सिर पर सजेगा प्रदेश अध्यक्ष का ताज

मध्यप्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष सहित जिला अध्यक्ष और संगठन के चुनावों की प्रक्रिया जारी है। हर राजनेता अपने चहेतों को विभिन्न पदों पर आसीन करने के लिये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश की नजर मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। वह इसलिये भी क्योंकि आगामी चार सालों के लिये जो रणनीति तैयार करना है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा हस्तक्षेप होता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का ताज वीडी शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सजता है। खैर, ताज किसी पर भी सजे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर खासी खींचतान है।

आखिर सागर जिले में इतनी खींचतान क्यों?

मध्यप्रदेश भाजपा के सागर जिले जनप्रतिनिधि पिछले कुछ दिनों से खासे उखड़े समझ आ रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पहले ही अपने नेताओं और सरकार पर फोन टेप कराये जाने का आरोप लगाया था उसके बाद भूपेन्द्र सिंह ने इस बात तो जिले की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने रखा था। उसके बाद अब गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव सहित अन्य राजनेताओं में सामंजस्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। सूत्रों के अनुसार सागर वालों के बीच में जो खींचतान चल रही है उसकी शिकायत पार्टी आलाकमान और संगठन में हुई है ऐसे में संगठन जल्द ही इस पर कोई एक्शन ले सकता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

MSP की गारंटी और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है।

सरकार को बातचीत करके अनशन खत्म करवाना चाहिए।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

एक तरफ मध्यप्रदेश के देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई। दूसरी तरफ ओडिशा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया है।

ये दोनों घटनाएं दुखद, शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय हैं।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

अपनी जनहित और जनकल्याण के कार्यों के लिये चर्चा का केन्द्र बनी आतिशी

समता पाठक/जगत प्रवाह

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की चर्चा हर तरफ हो रही है। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। आतिशी एक पढ़े- लिखे परिवार से आती है। इनके माता-पिता विजय सिंह और त्रिप्ता वाही दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनकी शुरूआती पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। जहां उन्होंने सिंगंडेल्स स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद, उन्होंने राधाकृष्णन-चेवनिंग छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। आतिशी ने रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शैक्षिक अनुसंधान में स्नातकोत्तर की डिग्री भी पूरी की हुई है। राजनीति में कदम रखने से पहले आतिशी ने एक स्कूल शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में भी काम किया है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनवरी 2013 में हुआ था। तभी ये आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ी थी। कई आन्दोलनों में इन्होने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतिशी ने नीति निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। खासकर भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अपने अनुभवों से। वर्तमान में आम आदमी पार्टी में रहते हुए ये शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पी.डब्ल्यू.डी., संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत है।

आतिशी दिल्ली के कालकाजी सीट से विधायक हैं। आतिशी के माता- पिता मार्क्स और लेनिन के विचारो से काफी ज्यादा प्रभावित थे इसीलिए आतिशी का पूरा नाम 'आतिशी मार्लेना' रखा गया है। जोकि मर्क्स और लेनिन के नामों का मिश्रण है। साल 2018 में, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से हटने और अपने काम को फोकस करने के लिए इन्होने मार्लेना नाम के आगे आतिशी रख लिया था।

दलित-आदिवासी उत्पीड़न की प्रयोगशाला बना मध्य प्रदेश

कमलनाथ
(मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता)

"अगर देश के किसी गाँव में किसी व्यक्ति को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया जाता है तो समझ लीजिए वहाँ आजादी नहीं पहुँची। वह गाँव आजाद नहीं है।" आजादी के कुछ वर्ष बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल क़िले की प्राचीर से यह बात कही थी। और आज भी देश या प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि किसी प्रदेश में दलितों और आदिवासियों की स्थिति कैसी है? कहीं उनके ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं? दुर्भाग्य से हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहाँ 20 वर्ष से भाजपा की सरकार है और जहाँ दलितों और आदिवासियों का सबसे अधिक उत्पीड़न हो रहा है।

इन अत्याचारों की मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही दलित, आदिवासी और संविधान विरोधी है। एक तरफ संसद में भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी राज में दलितों को लाठियों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। पुलिस कस्टडी में दलित आदिवासियों की मौत हो रही हैं। दलितों, आदिवासियों की कब्रगाह बना मध्यप्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामले में तीसरे स्थान पर है। पिछले दिनों शिवपुरी जिले के इंदरगढ़ गांव का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहाँ दबंगों ने दलित नारद जाटव को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक दलित बेटे की हत्या कर दी गई। इछावर में दलितों को मंदिर जाने से रोका गया। दलितों को आतंकित करने वाली ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन सरकार चुप्पी साधे है।

सतवास में दलित की हत्या पर सरकार मौन है। पिछले एक साल में प्रदेश में दलितों पर काफी अत्याचार हुए हैं। वह चाहे शिवपुरी की घटना हो या सागर की घटना हो। मध्यप्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिर में दलित युवती द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत से गुस्साए गुंडों ने युवती के भाई नितिन अहिरवार की पिछले वर्ष अगस्त माह में हत्या कर दी थी। हत्या में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी। पीड़ित परिवार समझौते के लिये तैयार नहीं हुआ तो दो दिन पूर्व पीड़िता के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। मंदसौर जिले के एक गांव में एक महिला का पीछा करने के आरोप में दलित व्यक्ति को चेहरा काला करके, गले में जूतों की माला डालकर घुमाया गया। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर साबित हो गया था कि प्रदेश में दलित वर्ग सुरक्षित नहीं है। यह दोनों घटनाएं तो सिर्फ ऐसी थी जो सुर्खियों में ज्यादा रहीं लेकिन ऐसी न जाने हजारों घटनाएं हैं जो रोज दलितों से साथ घट रही हैं।

हम जानते हैं कि प्रदेश में दलित आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। वे प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में निवासरत हैं। इन्हें भी आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन रोज आदिवासियों के शोषण की घटनाओं से तो यही लगता है कि भाजपा सरकार इन्हें अपना वर्ग मानती ही नहीं है।

अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में प्रदेश में एससी/एसटी एक्ट के तहत 02 हजार 627 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, दलितों पर अत्याचार के 07 हजार 214 मामले दर्ज किए गए।

ऐसे कई मामले सामने आए जो देश भर में चर्चा का विषय बने। इनमें सबसे ज्यादा सीधी के पेशाब कांड को लोग जानते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कर रहा था। दलितों पर अत्याचार के कई दूसरे मामले भी सामने आए जब मध्यप्रदेश में दलित और आदिवासियों के साथ अत्याचार किया गया था। दलितों और आदिवासियों के लिए काम करने वाले लोगों का मानना है कि इस तरह से यदि इनकी अस्मिता और अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा तो इनकी स्थिति और बदतर हो जाएगी। मध्य प्रदेश पहले ही महिला अत्याचार के मामलों के कारण शर्मसार होता रहा है।

देशभर में दर्ज हुए 10 हजार से अधिक मामले

देश भर में साल 2022 में एससी के खिलाफ अपराध के कम से कम 10,064 मामले दर्ज किए गए, जो 14.3% की वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ ही प्रदेश में इस केटेगरी में क्राइम रेश्यो साल 2021 में 8.4 फीसदी से बढ़कर साल 2022 में 9.6 हो गया है।

एससी अपराध की बात की जाए तो सामान्य चोट के 1607 मामलें और गंभीर चोट के 52 तो वहीं, हत्या के 61 मामले सामने आए है। देश का दुर्भाग्य है कि दलितों के साथ अपराध के मामलों में उच्च स्थान पर है।

यह स्थिति तब है, जब प्रदेश में भाजपा पिछले 20 वर्षों से सत्ता में है। भाजपा का शासन दलित-विरोधी नीतियों और संविधान-विरोधी सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अत्याचारियों को सजा देने के बजाय उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। यह लड़ाई अब केवल अन्याय के खिलाफ नहीं, बल्कि दलितों की गरिमा और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। पूरी कांग्रेस पार्टी इन अत्याचारों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और हर दलित भाई-बहन को न्याय दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करेगी। न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी।इन सब घटनाओं को लेकर कांग्रेस द्वारा संविधान की रक्षा के लिए 25 जनवरी 2025 को महू में 'जय भीम-जय संविधान, जय बापू' आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सभी सीडब्ल्यूसी मेंबर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

दुर्भाग्य की बात है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दलितों पर होने वाले अत्याचार और शोषण को लेकर कुछ भी कहने से बचते हैं। वे दलितों की सुरक्षा करना ही नहीं चाहते। प्रदेश का गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होने से दलित आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। यह मुख्यमंत्री का दायित्व है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर तुरंत संज्ञान लेना

एसटी क्राइम रेट में एनसीआरबी की रिपोर्ट

एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में आदिवासियों के ऊपर हुए अत्याचारों के 2979 मामले सामने आए जो कि पिछले साल के क्राइम के मुकाबले में 13 फीसदी अधिक थे। इसमें तीन साल से प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। 2,521 मामलों के साथ राजस्थान दूसरे और 742 मामलों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इन तीन सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।विजयपुर में विधानसभा उपचुनाव के दौरान आदिवासियों के घर जलाए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची ही नहीं है। राज्य में जो हत्याएं और यातनाएं हो रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बार-बार बेनकाब हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े कहते हैं कि पिछले तीन से चार साल में पांच लाख दलित और आदिवासी बहनें गायब हुई हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण की चीन ने चली चाल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

चीन ने भारत के साथ मधुर संबंध बनाने के बीच एक नई विस्तारवादी चाल चल दी। चीन ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को बनाने की स्वीकृति दे दी है। इस बांध परियोजना को दुनिया की सबसे बड़ी बांध संरचना परियोजना बताया जा रहा है। इसकी लागत का अनुमान 137 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह जानकारी चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अधिकारी ने देते हुए कहा है कि 'चीन सरकार ने यारलुंग जांग्बो नदी (ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम) के निचले क्षेत्रों में एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा। यहां ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ा मोड़ लेती हुई अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है। यह सामाचार हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा है। भारत के प्रति चीन का आचरण हमेशा ही संदिग्ध रहा है। चीन इस नाते अपने हितों और विकास के लिए जो भी निर्णय लेता है, वे सीमाई देशों के लिए संकट का सबब बन जाते हैं। ऐसी शंकाएं इसलिए पैदा होती हैं, क्योंकि चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में कभी गलवान में सैनिक घुसपैठ कराता है, तो कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गांव बसा देता है। उसके ये कृत्य उसकी साम्राज्यवादी मंशा उजागर करने वाले हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ा बांध बनाने की मंशा ने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि बांध में भरे पानी से चीन प्रतिवर्ष 300 अरब किलोवाट प्रतिघंटे बिजली पैदा करेगा। सिंचाई के लिए भी यह जल उपयोग में लाया जाएगा। इसके पहले से भी चीन ब्रह्मपुत्र के मूल उद्गम स्थल यारलुंग जांग्बो नदी पर 60 हजार मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र लगा रहा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह विशालकाय बांध के निर्माण में लगा है। आशंका है कि चीन इस बांध में भरे जाने वाले जल का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध जल युद्ध के रूप में कर सकता है। इसकी काट के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग क्षेत्र में 11,200 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। 1.10 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (पीएफआर) भी बन गई है।एक अन्य 9,380 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना अरुणाचल में पहले से ही निर्माणाधीन है।

इस पहल से चीन शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके को उपजाऊ भूमि में बदलना और इस क्षेत्र की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना चाहता है। दक्षिणी तिब्बत की यारलुंग जांग्बो नदी के जल प्रवाह को रेगिस्तान की ओर मोड़ा जाएगा। इसे मोड़ने के लिए चीन के अभियन्ता ऐसी तकनीकों के परीक्षण में जुटे हैं, जिनका प्रयोग कर ब्रह्मपुत्र नदी के जलप्रवाह को 1000 किमी लम्बी सुरंग बनाकर मोड़ दिया जाए। इस योजना के जरिए चीन की मंशा अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत से शिनजियांग में पानी ले जाने की है। भारत सरकार के साथ दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी चिन्तित हुए थे, क्योंकि सुरंग खुदाई से हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चीन ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कई बांध बनाए जाने को लेकर भारत बीजिंग को पहले ही अपनी चिन्ताओं से अवगत करा चुका है।

ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर चीन का भारत से ही नहीं बांग्लादेश से भी विवाद है। इस नदी पर कई बांध बनाकर चीन ने ऐसे जल प्रबन्ध कर लिये हैं कि वह जब चाहे तब भारत और बांग्लादेश में पानी के प्रवाह को रोक दे और जब चाहे तब ज्यादा पानी छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दे। चीन ने ऐसी हरकत करते हुए साल 2016 में भारत में जलापूर्ति करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जियाबुकू का पानी रोक भी दिया था।चीन यदि बांधों से ज्यादा पानी छोड़ देता है तो यह पूर्वोत्तर भारत की कृषि व्यवस्था तहस नहस कर सकता है। चीन के बांध भारत की पर्यावर्णीय व्यवस्था पर भी विपरीत असर डाल सकते हैं।

एशिया की सबसे लम्बी इस नदी की लम्बाई 3000 किमी है। इसी की सहायक नदी जियाबुकू है। जिस पर चीन हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है। दुनिया की सबसे लम्बी नदियों में 29वाँ स्थान रखने वाली ब्रह्मपुत्र 1625 किमी तिब्बत क्षेत्र में बहती है। इसके बाद 918 किमी भारत और 363 किमी की लम्बाई में बांग्लादेश में बहती है। समुद्री तट से 3300 मीटर की ऊँचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बहने वाली इस नदी पर चीन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीन पनबिजली परियोजनाएँ निर्माण के प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर चुका है और अब नए बांध निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन इन बाँधों का निर्माण अपनी आबादी के लिये व्यापारिक, सिंचाई, बिजली और पेयजल समस्याओं के निदान के उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन उसका इन बाँधों और जल सुरंगों के निर्माण की पृष्ठभूमि में छिपा एजेंडा, खासतौर से भारत के खिलाफ जल हथियार के रूप में रणनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है? दरअसल चीन में बढ़ती आबादी के चलते इस समय 886 शहरों में से 110 शहर पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। उद्योगों और कृषि सम्बन्धी जरूरतों के लिये भी चीन को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत है। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी का अनूठा इस्तेमाल करते हुए अपने शिनजियांग, जांझु और मंगोलिया इलाकों में फैले व विस्तृत हो रहे रेगिस्तान को भी नियंत्रित करना चाहता है। चीन की यह नियति रही है कि वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये पड़ोसी देशों की कभी परवाह नहीं करता।चीन ब्रह्मपुत्र के पानी का मनचाहे उद्देश्यों के लिये उपयोग करता है तो तय है, अरुणाचल में जो 17 पनबिजली परियोजनाएँ प्रस्तावित व निर्माणाधीन हैं, वे सब अटक प्रभावित हो सकती हैं? ये परियोजनाएँ पूरी हो जाती हैं और ब्रह्मपुत्र से इन्हें पानी मिलता रहता है तो इनसे 37,827 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बिजली से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बिजली की आपूर्ति तो होगी ही, पश्चिम बंगाल और ओड़ीसा को भी अरुणाचल बिजली बेचने लग जाएगा। चीन अरुणाचल पर जो टेढ़ी निगाह बनाए रखता है, उसका एक बड़ा कारण अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र की जलधारा ऐसे पहाड़ व पठारों से गुजरती है, जहाँ भारत को मध्यम व लघु बाँध बनाना आसान है। ये सभी बाँध भविष्य में अस्तित्व में आ जाते हैं और पानी का प्रवाह बना रहता है तो पूर्वोत्तर के सातों राज्यों की बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसे बुनियादी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

चीन के साथ सुविधा यह है कि वह अपनी नदियों के जल को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर चलता है। पानी को एक उपभोक्ता वस्तु मानकर वह उनका अपने हितों के लिये अधिकतम दोहन में लगा है। बौद्ध धर्मावलम्बी चीन परम्परा और आधुनिकता के बीच मध्यमार्गी सामंजस्य बनाकर चल रहा है। जो नीतियाँ एक बार मंजूर हो जाती हैं, उनके अमल में चीन कड़ा रुख और भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाता है। इसलिये वहाँ परियोजना के निर्माण में धर्म और पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ रोड़ा नहीं बनती। नतीजतन एक बार कोई परियोजना कागज पर आकार ले लेती है तो वह आरम्भ होने के बाद निर्धारित समयावधि में लगभग पूरी हो जाती है। चीन और भारत के बीच ब्रह्मपुत्र के जल-बँटवारे को लेकर विवाद और टकराव बढ़ रहा है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पानी के उपयोग को लेकर कई संधियाँ हुई हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की पानी के उपभोग को लेकर 1997 में हुई संधि के प्रस्ताव पर अमल किया जाता है।इस संधि के प्रारूप में प्रावधान है कि जब कोई नदी दो या इससे ज्यादा देशों में बहती है तो जिन देशों में इसका प्रवाह है, वहाँ उसके पानी पर उस देश का समान अधिकार होगा। इस लिहाज से चीन को सोची-समझी रणनीति के तहत पानी रोकने या उसकी धारा बदलने का अधिकार है ही नहीं। इस संधि में जल प्रवाह के आँकड़े साझा करने की शर्त भी शामिल है। लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र की इस संधि की शर्तों को मानने के लिये इसलिये बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इस संधि पर अब तक चीन और भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं।

2013 में एक अन्तर मंत्रालय विशेष समूह गठित किया गया था। इसमें भारत के साथ चीन का यह समझौता हुआ था कि चीन पारदर्शिता अपनाते हुए पानी के प्रवाह से सम्बन्धित आँकड़ों को साझा करेगा। लेकिन चीन ने इस समझौते का पालन नहीं किया। जबकि चीन अपने पड़ोसी देश लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम से मेकांग नदी पर बने बांधों के आंकड़े साझा करता है। इस नदी पर चीन ने 11 बांध बना लिए हैं। चीन जब चाहे तब ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देता है, अथवा इकट्ठा छोड़ देता है। इस चालाकी के चलते अरुणाचल में जो बाढ़ें आई हैं, उनकी पृष्ठभूमि में चीन द्वारा बिना किसी सूचना के पानी छोड़ा जाना रहा है। अतएव इस नए बांध के निर्माण के बाद यदि चीन के साथ गलवान और डोकलाम की तरह भू-राजनीतिक विवाद उत्पन्न होता है तो चीन प्रतिक्रिया शुरू इस बांध के जल को नियंत्रित या अधिक मात्रा में छोड़कर भारतीय राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है।

गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ झांकियों का होगा

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले में गणतंत्र दिवस गरिमापूर्ण तरीके से व समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस लाइन ग्राउंड नर्मदापुरम में आयोजित किया जायेगा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय आयोजन के लिए की जाने वाली तैयारियां की समीक्षा की गई तथा उपस्थित अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में दायित्व सौंपे। बैठक में अपर कलेक्टर सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शासकीय कार्यालयों मे ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ध्वजारोहण के दौरान ध्वज संहिता का पालन कराएं। अपर कलेक्टर सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय सीमा में पूर्ण करें। बैठक में जिला स्तरीय कार्यक्रम में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था का दायित्व नगर पालिका नर्मदापुरम को सौंपा गया। बेरीकेटिंग के लिए बांस व बल्लीयों की व्यवस्था वन विभाग करेगा तथा बैठक व्यवस्था नगर पालिका व लोक निर्माण विभाग करेंगे। अपर कलेक्टर सिंह ने पुलिस परेड ग्राउंड के समतलीकरण, सेक्टर निर्माण, ध्वजारोहण, माइक एवं बिजली व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की समीक्षा कर सुव्यवस्थित तैयारियां करने के निर्देश दिए।गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ विद्यार्थियों द्वारा पीटी प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा तथा आकर्षक परेड भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम स्थल पुलिस लाइन में 24 जनवरी को फाइनल रिहर्सल की जायेगी।

स्वामी विवेकानंद के आदर्शों ने आधुनिक भारत को दी नई दिशा

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के आध्यात्म, शिक्षा और स्वाभिमान को विश्व पटल पर अंकित किया। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरू के रूप में स्वामी विवेकानंद का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन के कारण हुआ। इस उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद द्वारा सभी को ''भाईयों एवं बहनों'' कहकर संबोधित किए जाने ने सभी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे संत रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 1984 को युवा दिवस की घोषणा की गई थी। इसके बाद से हर साल इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता जिसने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी हो। उन्होंने हमें जो स्वाभिमान दिया है वह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर हमारे अंदर आत्मसम्मान और अभिमान जगा देता है। स्वामीजी ने जो लिखा वह हमारे लिए प्रेरणा है। यह आने वाले लंबे समय तक युवाओं को प्रेरित व प्रभावित करता रहेगा।

करीब 118 वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो में हुए उनके भाषण को आज भी याद किया जाता है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के वे आदर्श प्रतिनिधि हैं, जिनकी प्रेरणाएं हमें आज भी मार्ग दिखाती हैं। शिकागो में जब विवेकानंद को दुनिया ने सुना तो जाना कि भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है जो दिशाहारा मानवता को सही दिशा देने में समर्थ है। शिकागो में विवेकानंद ने कहा था "मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि, हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी"।

इसका अर्थ यह है कि विवेकानंद भी भारत की सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को दुनिया से परिचित कराने में विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान था। 11 सितंबर 1893 का वह दिन विश्व के इतिहास में अविस्मरणीय बन गया जब शिकागो में विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया। उसके बाद से ही विवेकानंद के सिद्धांतों को दुनिया समझने की कोशिश करती रही लेकिन समझ में आया। 118 वर्ष बाद, जब 11 सितंबर 2001 की सुबह अल-कायदा के 19 आतंकियों ने उसी अमेरिका के ट्विन टॉवर्स को ध्वस्त करके मानवता को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया जिस अमेरिका में सार्वभौमिक सहिष्णुता की बात विवेकानंद ने की थी। इसीलिए 11 सितंबर की तारीख जहां विश्व में विवेकानंद के मुख से निकले सार्वभौमिक सहिष्णुता के सिद्धांत की दृष्टि से अभूतपूर्व है तो वह तारीख सबसे बड़े आतंकी हमले में उस सिद्धांत को आघात पहुंचाने की दृष्टि से भी अविस्मरणीय है।

विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है लेकिन विवेकानंद के सिद्धांत पूरी दुनिया में 12 महीनों के 365 दिन प्रासंगिक हैं। जिस वेदांत को उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में रचा उसे उन्होंने जीवन पर्यंत अपनाया भी। वेदांत एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवहारिकता के रूप में विवेकानंद के जीवन में था। इसीलिए अपने छोटे से जीवन काल में विवेकानंद इतना प्रभाव उत्पन्न कर पाए। उन्होंने भारतीय वांग्मय और भारतीय धर्म-संस्कृति का ही विश्व को परिचय नहीं कराया बल्कि सार्वभौमिक सहिष्णुता के उस सिद्धांत को संसार के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश भी की। आज 02-02 विश्व युद्ध के बाद, सारे संसार में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद के खतरों के बाद यदि किसी सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है तो वह सार्वभौमिक सहिष्णुता का सिद्धांत ही है जो एक तरफा नहीं है। बल्कि जिसे दोनों तरफ से निभाने की आवश्यकता है। विवेकानंद की जयंती पर जरूरत है प्रज्ञावान बनने की, स्वयं को पहचानने की, अपनी आयु से ऊपर उठकर विचार करने की। आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जयंती की अनेकानेक शुभकामनाएं।

डॉ. सुरेंद्र कुमार पाठक "ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन एडवोकेसी अवार्ड" से सम्मानित

-संवाददाता

जगत प्रवाह. नई दिल्ली। शिक्षा और शांति निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाले डॉ. सुरेंद्र कुमार पाठक को 20वें वर्ल्ड पीस कांग्रेस के अवसर पर ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन एडवोकेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 29-31 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ। यह सम्मान इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस (IAEWP) द्वारा जीपीएफ-इंडिया, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ और अन्य प्रमुख संस्थाओं के सहयोग से प्रदान किया गया। यह पुरस्कार शांति शिक्षा, सतत विकास, और वैश्विक समरसता के क्षेत्र में डॉ. पाठक के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। कार्यक्रम में डॉ. पाठक के कार्यों को सराहते हुए बताया गया कि उन्होंने शिक्षा और शांति के माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी, असहिष्णुता और समाज में स्थिरता लाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। उनका कार्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरणादायक है। इस विशेष अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे, जिनमें डॉ. प्रियरंजन त्रिवेदी (IAEWP के अध्यक्ष), डॉ. श्याम एन. पांडे (टीजीओयू के कुलपति), डॉ. मार्कंडेय राय (जीपीएफ-इंडिया के अध्यक्ष), और डॉ. प्रीतम बी. शर्मा (वर्ल्ड एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष) शामिल थे।

आयोजकों ने इस कार्यक्रम में वसुधैव कुटुंबकम् की विचारधारा पर जोर देते हुए इसे अधिक समरस और जुड़ा हुआ वैश्विक समाज बनाने का माध्यम बताया। उन्होंने डॉ. पाठक के कार्यों की सराहना की, जो स्वच्छ, हरित और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। यह सम्मान डॉ. सुरेंद्र कुमार पाठक की शिक्षा को शांति और स्थिरता के माध्यम के रूप में उपयोग करने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों को प्रेरित करता है।

एम्स भोपाल में दुर्लभ एड्रिनल ट्यूमर को हटाने के लिए सफल सर्जरी

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल ने कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हाल ही में, संस्थान ने 27 वर्षीय पुरुष मरीज के शरीर से एक दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण एड्रिनल ट्यूमर, जिसे फियोक्रोमोसाइटोमा कहा जाता है, को सफलतापूर्वक निकाला। यह ट्यूमर दो प्रमुख रक्त वाहिकाओं– इन्फीरियर वेना कावा (आईवीसी) और एओर्टा – के पीछे स्थित था, जो हृदय से रक्त के प्रवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन वाहिकाओं की नाजुक स्थिति और ट्यूमर की संवेदनशीलता के कारण यह सर्जरी अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। फियोक्रोमोसाइटोमा एक दुर्लभ ट्यूमर है जो किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथियों में विकसित होता है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा राजिम कुंभ कल्पः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित बैठक कक्ष में राजिम कुंभ कल्प के तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम समेत कुंभ कल्प के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प 2025 धर्म, आस्था और संस्कृति का अद्भुत समागम होगा और यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित करने का भी सुंदर माध्यम है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रद्धालुओं को यहां अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त हो और यह आयोजन हमारी गौरवशाली विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री साय ने राजिम कुंभ कल्प के आयोजन में शामिल समस्त विभागों और प्रशासनिक अमले को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने

12 से 26 फरवरी तक आयोजित होगा राजिम कुंभ कल्प

श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी उपाय और स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। श्री साय ने कहा कि "हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आयोजन को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में इसे स्थापित करें। उन्होंने 12 फरवरी को आयोजित माघी पुन्नी स्नान, 21 फरवरी जानकी जयंती के अवसर पर संत समागम और 26 फरवरी को होने वाले शाही स्नान की तैयारी पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री साय को अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने राजिम कुंभ कल्प 2025 के आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से आयोजन स्थल में विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित स्थानों के बारे में बताया। कुंभ कल्प में नागरिक सुविधाओं, साधु संतों के आवागमन, शाही स्नान और गंगा आरती को लेकर विभाग के तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा। राजिम कुंभ कल्प के संपूर्ण आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को नोडल बनाया गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ कल्प में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी साधु संतों का विराट समागम होगा। माघी पुन्नी स्नान, शाही स्नान, जानकी जयंती के अवसर पर संत समागम विशेष रूप से आयोजित होगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, मेला, मड़ई, मीना बाजार और विभागीय प्रदर्शनी भी कुंभ कल्प का विशेष आकर्षण के रूप में शामिल हैं।

पत्रकारों का महाअधिवेशन धार्मिक नगरी आलोट में

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. दिलहरी। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत एवं श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन 12 जनवरी 2025 को स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में होगा जिसमें मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र, अध्यक्षता जितेन्द्र सिंह गेहलोत, विशेष अतिथि श्रीमती लाला बाई शम्भू लाल जिला पंचायत अध्यक्ष, रतलाम, विशिष्ट अतिथि उपेन्द्र सिंह यादव संरक्षक राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत, विशेष अतिथि दलजीतसिंह गुरुदा प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत, के सी यादव महानिर्यंत्रक राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत, दीपक जैन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ नंदन, राज जैन विधानसभा प्रभारी, श्रीमती ममता विमल जैन अध्यक्ष नगर पालिका आलोट, मुकेश परमार नगर पालिका अध्यक्ष, ताल, जितेन्द्र सोनी प्रधान संपादक लोकसखामी मनीष सेठिया अध्यक्ष गोरधन गौशाला आलोट, राम चन्द्र शर्मा मीसाबंदी अध्यक्ष ताल उपस्थित रहेंगे। इस महाअधिवेशन में अधिक से अधिक पत्रकार साथियों से अपील की है अपीलकर्ता प्रमोद बरसले प्रदेश महासचिव रामचंद्र गिनारेअशोक मूंदड़ा मुकेश परदेशी ब्रजेश रिछारिया मनोज कुशवाह कपिल जागरवा अध्यक्ष आलोट फिरोज शाह सचिव आलोट राजाराम डायरी उपाध्यक्ष ताल तथा अन्य पत्रकारों ने महाअधिवेशन में शामिल होने की अपील की है।

RO No : 13057/195

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)